down telecom tariff ensuring minimum cost of communications; and

(b) if so, the action taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) There is no such proposal at present.

(b) Does not arise in view of (a) above.

डाक व तारघरों की आवश्यकता

3727. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्धारित मानदंडों के अनुसार भारत में कितने डाक व तारघरों की आवश्यकता है तथा वर्तमान में विभिन्न राज्यों में कार्यरत डाक व तारघरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में डाक व तार घरों का आज भी अत्यधिक अभाव है तथा वे राष्ट्र की मुख्य धारा की तुलना में पिछड़ रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने मांग और उपलब्धता के बीच अंतर को कम करने के लिए कोई योजना बनायी है; और

(घ) क्या गुजरात, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में डाक व तार घरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) दूरी और जनसंख्या के दो मानदंडों के आधार पर जिन गांवों में डाकघर खोलने का औचित्य बनता है, उनकी संख्या लगभग 6000 है। आय संबंधी तीसरे मानदंड की जांच तब की जाती है जब एक ठोस प्रस्ताव तैयार किया जाता है। कार्य कर रहे डाकघरों का सर्किलवार ब्यौरा **विवरण-I** में दिया गया है **(नीचे देखिये)**।

इस समय विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे तारघरों की संख्या का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। **(नीचे देखिये)**।

(ख) से (घ) जब डाकघर खोलने संबंधी लक्ष्य नियत किए जाते हैं, तब ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों पर यथोचित विचार किया जाता है। जनजातीय, पहाड़ी और पिछड़े इलाकों में डाकघर खोलने के लिए मानदंडों को और अधिक शिथिल किया गया है। वार्षिक योनजा 1998-99 के दौरान देश भर में 648 डाकघर खोलने का लक्ष्य है और ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनमें जनजातीय क्षेत्र भी शामिल हैं, 598 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोले जायेंगे। उक्त अवधि के दौरान खोले गए कुछ विभागीय उपडाकघर भी ग्रामीण क्षेत्र में ही आते हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान गुजरात, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में डाकघर खोलने संबंधी लक्ष्य इस प्रकार हैं:—

गुजरात	उड़ीसा	मध्य प्रदेश
42	12	52

तारघर खोलना परियात पर निर्भर करता है। यदि परियात की व्यूनतम संख्या उपलब्ध है तो इसकी योनजा बनाई जाती है।

विवरण-I

डाकघरों का सर्किलवार और श्रेणीवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	प्रधान डाकघर (एचओ)	विभागीय उपडाकघर (डीएसओ)	अतिरिक्त विभागीय उपडाकघर (ईडीएसओ)	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ईडीबीओ)	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	124	2358	53	13657	16172
2.	असम	16	584	36	3182	3818
3.	बिहार	42	1436	127	10200	11805
4.	दिल्ली	9	413	21	113	556
5.	गुजरात	42	1373	46	7501	8962
6.	हरियाणा	15	459	14	2115	2603

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	प्रधान डाकघर (एचओ)	विभागीय उपडाकघर (डीएसओ)	अतिरिक्त विभागीय उपडाकघर (ईडीएसओ)	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ईडीबीओ)	कुल
7.	हिमाचल प्रदेश	18	443	18	2273	2752
8.	जम्मू एवं कश्मीर	9	240	31	1328	1608
9.	कर्नाटक	69	1775	297	7665	9806
10.	केरल	51	1456	523	3012	5042
11.	मध्य प्रदेश	52	1372	98	9719	11241
12.	महाराष्ट्र	63	2186	132	10193	12574
13.	उत्तर-पूर्व	9	308	20	2487	2824
14.	उड़ीसा	35	1160	195	6694	8084
15.	पंजाब	22	803	11	3065	3901
16.	राजस्थान	55	1392	103	8756	10306
17.	तमिलनाडु	92	2762	219	9034	12107
18.	उत्तर प्रदेश	86	2836	458	16703	20083
19.	पश्चिम बंगाल	42	1668	358	6805	8777
	कुलः	835	25024	2760	124402	153021

विवरण-II

इस समय देश के विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे तारघरों/संयुक्त डाक-तारघरों की संख्या

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	तारघरों की संख्या	संयुक्त डाक-तारघरों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	124	3834
2.	असम	29	748
3.	अरूणाचल प्रदेश	3	25
4.	बिहार	59	4219
5.	दिल्ली	30	5
6.	गुजरात	40	2247
7.	गोआ	4	71
8.	हिमाचल प्रदेश	13	1242
9.	हरियाणा	17	376
10.	जम्मू एवं कश्मीर	9	138
11.	कर्नाटक	69	5036
12.	केरल	39	1985

1	2	3	4
13.	महाराष्ट्र	96	2792
14.	मध्य प्रदेश	67	2344
15.	उड़ीसा	29	3524
16.	पंजाब	22	239
	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	2	5
17.	मेघालय	2	71
18.	मिजोरम	1	9
19.	मणिपुर	2	47
20.	नागालैंड	2	26
21.	त्रिपुरा	3	73
22.	राजस्थान	47	2258
23.	तमिलनाडु	107	6536
	पांडिचेरि (संघ शासित क्षेत्र)	1	11
24.	उत्तर प्रदेश	105	5388
25.	सिक्किम	2	44
26.	पश्चिम बंगाल	45	1926

Programmes Implemented in Telecommunication and Postal Sector

3728. SHRI ANANTRAY DEV. SHANKER DAVE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the names of the programmes implemented in the telecommunication and Postal sectors in the Country, particularly in the state of Madhya Pradesh during the Eighth Five Year Plan period;

(b) the achievements of the programmes implemented so far;

(c) the district-wise amounts of the Central Assistances sanctioned for the Malwa region particularly for the Vidisha district under the said programme; and

(d) the steps taken to further strengthen this programmes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) and (b) the names of the Schemes implemented in the country and in Madhya Pradesh during the Eighth Five Year Plan period and the achievements in this regard during 1997-98 and up to 30th June during 1998-99 are given in Statement-I *(See below)*.

Information in this regard of the Postal sector is given in Statement-III *(see below)*.

Amounts spent in Malwa Region, district-wise, during the Eighty Five Year Plan and during 1997-98 are given in Statement-II *(see below)*.

Information in this regard of the Postal sector is given in Statement-III B *(see below)*.

(d) 1.10 lakh now telephone connections are planned for Madhya Pradesh, including 40,800 lines for Malwa Region, during 1998-99.

Information in this regard of the Postal sector is given in Statement—IIIC *(See below)*.